

राजस्थान की प्राथमिक शिक्षा में भाषा अधिगम और संख्यात्मक क्षमता का विकास

संगीता कंवर
शोधार्थी
शिक्षा विभाग
अपेक्स विश्वविद्यालय, जयपुर

सार संक्षेप

प्राथमिक शिक्षा के प्रथम वर्षों में भाषा अधिगम और संख्यात्मक क्षमता का विकास शैक्षिक और सामाजिक-आर्थिक प्रगति के लिए आधारशिला है। भारत जैसे बहुभाषी और विविध सामाजिक पृष्ठभूमियों वाले देश में, ये दोनों कौशल अक्सर बच्चों के पारिवारिक, शैक्षिक और नीतिगत परिवेश से प्रभावित होते हैं। इस लेख में अध्ययनों और नीति दस्तावेजों के माध्यम से यह विश्लेषण किया गया है कि भाषा अधिगम और संख्यात्मक क्षमता कैसे विकसित होती है, किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, किन-किन सर्वश्रेष्ठ विधियों ने असर दिखाया है, और नीतिगत उपायों से कैसे सुधार संभव है। शोध बताते हैं कि मातृभाषा में शिक्षा, प्रारंभिक शैक्षणिक संसाधन, शिक्षक प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम की निरंतरता और अभिभावक-परिस्थिति विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। नीति-स्तर पर निपुण भारत (NIPUN Bharat), NEP 2020 जैसी पहलें सकारात्मक कदम हैं, किन्तु उनका असर क्षेत्र-विशेष, भाषा विविधता, संसाधन असमानता व स्कूल प्रवेश की तैयारी पर आधारित चुनौतियों से सीमित है। लेख के अंत में सुझाव दिए गए हैं कि शिक्षा नीति, शिक्षक विकास, मूल्यांकन पद्धति, और परिवार-समुदाय सहभागिता को मिलाकर एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया जाए जिससे भाषा अधिगम और संख्यात्मक क्षमता का विकास अधिक समावेशी और प्रभावी हो सके।

परिचय

भारत में प्राथमिक शिक्षा की दिशा बदली है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में भाषा अधिगम और संख्यात्मक क्षमता को शिक्षा नीतियों की सर्वोच्च प्राथमिकता मिल रही है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP-2020) ने यह निर्धारित किया है कि सभी बच्चों को कक्षा तीन के अंत तक मूल भाषा पढ़ने-समझने और बुनियादी गणितीय कार्यों में सक्षम होना चाहिए। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जुलाई 2021 में NIPUN Bharat मिशन की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य है कि पूर्व-विद्यालय से लेकर कक्षा 3 तक के 3-9 वर्ष की आयु के बच्चों के बीच भाषा एवं संख्यात्मक कौशलों को व्यवस्थित तरीके से विकसित किया जाए।^{1,2} इस पहल में शिक्षक प्रशिक्षण, बच्चों के लिए अनुकूल शिक्षण सामग्री, फॉर्मेटिव मूल्यांकन और अभिभावकों एवं समुदाय की भागीदारी को प्रमुख घटकों के रूप में शामिल किया गया है।³

राजस्थान में भी ये राष्ट्रीय प्रयत्न असर दिखाने लगे हैं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में। ASER-2024 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में कक्षा III के बच्चों में जो प्रतिशत बच्चे कक्षा II स्तर की पाठ्य सामग्री पढ़ने में सक्षम हैं, वह समय के साथ बदल रहा है, यद्यपि अपेक्षित लक्ष्य अभी दूर है। इसके अलावा अध्ययनों ने यह दिखाया है कि बच्चे जिन क्षेत्रों में पाठ्य-पुस्तकें, भाषा-सम्बंधित गतिविधियाँ और

संख्यात्मक अभ्यास जीवन-अनुभव से जुड़े हों, वहां सीखने की दर बेहतर होती है। परंतु भाषा विविधता, मातृभाषा-माध्यम की अनुपस्थिति, शिक्षण संसाधनों की कमी और प्रारंभिक वर्षों में स्कूल प्रवेश के समय बच्चों का तैयार न होना जैसी चुनौतियाँ राजस्थान में अभी भी स्पष्ट रूप से मौजूद हैं। इसके चलते राज्य सरकार की कुछ विशेष पहलें शुरू हुई हैं जैसे किसान अभियांत्रण, आंगनबाड़ी-प्रबोधन, भाषा-मैपिंग सर्वेक्षण आदि – ताकि भाषा अधिगम और संख्यात्मक कौशलों को स्थानीय संदर्भों के अनुरूप सुदृढ़ किया जा सके।

राजस्थान में भाषा अधिगम का विकास

भाषा अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बच्चे भाषा की ध्वनियों, शब्दों, व्याकरण, अर्थ और प्रयोग को सीखते हैं। छुटपन से ही सुनने-बोलने-अनुभव से शुरू होकर, बच्चों का भाषा विकास क्रमबद्ध और अनुभव-आधारित होता है। राजस्थान में भाषा अधिगम के विकास की स्थिति की जानकारी ASER रिपोर्ट, भाषा-मैपिंग सर्वेक्षण और राज्य-नीतियों से मिलती है, जिसमें कुछ प्रगति के साथ अभी भी महत्वपूर्ण चुनौतियाँ नज़र आती हैं। रूरल राजस्थान ASER-2022 रिपोर्ट के अनुसार, सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 5 के बच्चों में जो प्रतिशत बच्चे कक्षा 2 स्तर के पाठ पढ़ सकते थे, वह 2018 में लगभग 49.1 प्रतिशत था, लेकिन 2022 में यह घट कर 38.2 प्रतिशत हो गया। इसी तरह, कक्षा 3 के बच्चों में भी पाठ पढ़ने की क्षमता में गिरावट हुई है: कक्षा 2 लेवल की टेक्स्ट पढ़ने वाले बच्चों का प्रतिशत लगभग 20.4 प्रतिशत से घट कर 14.2 प्रतिशत रह गया।⁴ यह संकेत है कि शुरुआती वर्षों में भाषा अधिगम की गुणवत्ता और निरंतरता में कमी आई है। इस कमी के पीछे कई कारण हैं जैसे कि बच्चों को स्कूल में प्रवेश करते समय भाषा-वातावरण की कमी, मातृभाषा-माध्यम की अनुपस्थिति, शिक्षण सामग्री और अध्यापक प्रशिक्षण की सीमाएँ।⁵

राजस्थान सरकार ने भाषा अधिगम की स्थिति सुधारने के लिए कुछ सक्रिय कदम उठाए हैं। उदाहरण के लिए, RSCERT ने भाषा-मैपिंग सर्वेक्षण किया है जिसमें पता चला है कि राज्य के विभिन्न जिलों में विभिन्न बोलियाँ और मातृभाषाएँ उपयोग में हैं, और इनका स्कूलों में पढ़ाई के भाषा-माध्यम से तालमेल बनाने के प्रस्ताव चल रहे हैं।⁶ सरकार ने प्राथमिक कक्षाओं (कक्षा 1 से 5) के लिए स्थानीय बोलियों/भाषाओं को Medium of Instruction के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है, और लगभग 18 बोलियों को पाठ्य-शिक्षण में शामिल करने की योजना बनी है।⁷ इसके अतिरिक्त मातृभाषा-आधारित पढ़ाई से शिक्षा में भागीदारी, उपस्थिति और समझ में वृद्धि होने की संभावनाएँ बतायी जा रही हैं, विशेषकर आदिवासी एवं बहुभाषी इलाकों में जहाँ स्कूल भाषा और बच्चों की मातृभाषा में अंतर पारंपरिक चुनौतियाँ पैदा करता है।⁸

इन आँकड़ों और पहलों से स्पष्ट है कि राजस्थान में भाषा अधिगम के मूल स्तरों में सुधार की दिशा में प्रयास हो रहे हैं, लेकिन अभी भी प्रारंभिक शिक्षा के चरणों में भाषा समझ और उपयोग की तुलना में अपेक्षाएँ अधिक हैं। यदि स्थानीय भाषाओं का प्रयोग, अध्यापक प्रशिक्षण एवं शिक्षण सामग्री को मातृभाषा और क्षेत्रीय बोलियों के अनुरूप सुधारा जाए, तो भाषा अधिगम की प्रक्रिया अधिक सशक्त और समावेशी हो सकती है।

राजस्थान में संख्यात्मक क्षमता का विकास

संख्यात्मक क्षमता का विकास एक क्रमबद्ध एवं अनुभव-आधारित प्रक्रिया है, जिसकी शुरुआत बचपन के शुरुआती वर्षों से होती है। इन वर्षों में बच्चे संख्या-पहचान, मात्रा की तुलना, आकार और आकृति की समझ, मापन, जोड़-घटाव आदि अवधारणाएँ अपनी सहज बुद्धि के माध्यम से विकसित करते हैं। उदाहरण स्वरूप, जब बच्चे गिनती सीखते हैं, वस्तुओं को क्रमबद्ध करते हैं, आकृतियों (जैसे वृत्त, वर्ग, त्रिकोण आदि) को पहचानते हैं, तब उनके मस्तिष्क में संख्यात्मक अवयवों की आधारशिला स्थापित होती है। ये प्रारंभिक अनुभव बाद में प्रतीकात्मक गणित जैसे अंक, संक्रियाएँ, अनुपात आदि की ओर बढ़ने का मार्ग बनाते हैं।

राजस्थान समेत भारत के कुछ राज्यों में Pathways to Numeracy (P2N) अध्ययन का हिस्सा है, जिसमें प्री-स्कूल और कक्षा 1 की पाठ्य-पुस्तकों एवं शैक्षिक सामग्री में प्री-न्यूमेरसी और प्रारंभिक गणितीय अवधारणाएँ कितनी शामिल हैं, इसका विश्लेषण किया गया है। P2N शोध में यह पाया गया कि राजस्थान की पाठ्य-सामग्री में गिनती, मापन, पैटर्न, आकृतियाँ आदि गतिविधियाँ मौजूद हैं, लेकिन अक्सर ये गतिविधियाँ पर्याप्त नहीं होतीं या उनमें कठिनाई की वृद्धि क्रमबद्ध नहीं होती।⁹ ये दिखाता है कि संख्यात्मक क्षमता की नींव मजबूत करने के लिए गतिविधि-आधारित शिक्षण, और संसाधनों की स्थिर उपलब्धता की ज़रूरत है।

राजस्थान पर PARAKH राज्य परीक्षा और अंतःशिक्षण सर्वेक्षण के ताजा परिणामों से पता चलता है कि राज्य सरकार द्वारा संचालित स्कूलों के छात्रों ने गणित में राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं – सरकार द्वारा निर्धारित गुणवत्ता-मानकों पर राज्य की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर मानी जाती है। उदाहरण के लिए, ग्रेड 6 के छात्रों में, राजस्थान के स्थानीय सरकारी स्कूलों ने गणित में राष्ट्रीय औसत से लगभग 7 प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किए हैं।¹⁰ साथ ही, राज्य के विद्यालयों में ग्रामीण छात्रों की गणित में उपलब्धि शहरी छात्रों से अपेक्षाकृत कम नहीं है, कभी-कभी ग्रामीण इलाकों में ग्रामीण छात्रों ने राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन किया है। फिर भी, सुधार की गति धीमी है और कई आवश्यक क्षेत्रों में ध्यान देने की ज़रूरत है। शुरुआत-कक्षाओं (प्री-स्कूल, कक्षा 1-2) में संख्यात्मक अवधारणाओं का पर्याप्त अनुभव नहीं मिलना, शिक्षक प्रशिक्षण की कमी, हस्त-गत/मॉडल उपकरण और गतिविधि-आधारित शिक्षण संसाधन की अनुपलब्धता आदि प्रमुख अवरोध हैं। सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ, भाषा बाधाएँ, विद्यालयों में बड़े-छोटे कक्षाओं के आकार आदि भी प्रभाव डालती हैं। यदि राज्य इन पहलुओं में निरंतर सुधार करे कृ विशेष रूप से प्रारंभिक वर्ष की शिक्षा, शिक्षक समर्थन और संसाधन वितरण में – तो संख्यात्मक क्षमता के विकास में और बेहतर परिणाम आ सकते हैं।

वर्तमान स्थिति और चुनौतियाँ

भारत में अनेक राज्यों और क्षेत्रों में भाषा अधिगम और संख्यात्मक कौशलों के विकास की स्थिति मिश्रित है। अधिकांश राज्य Grade 1 में जैसे ही अंकगणित, संख्या अवधारणाएँ पर जोर देते हैं, प्री-स्कूल में विकसित प्री-न्यूमेरसी अनुभवों की निरंतरता कम होती है। साथ ही, कई बच्चों के लिए school readiness की स्थिति कम होती है; अर्थात् वे प्री-स्कूल या घर से पर्याप्त भाषा, संख्या और सामाजिक-संज्ञानात्मक अनुभव न प्राप्त कर के प्राथमिक विद्यालय में आते हैं। राजस्थान की प्राथमिक शिक्षा में भाषा अधिगम और संख्यात्मक क्षमता की विकास की स्थिति में कुछ प्रगति हुई है, पर अभी भी कई चुनौतियाँ बरकरार हैं।

- **शिक्षण परिणाम और FLN स्तर:** राज्य की ग्रामीण सरकारी स्कूलों में कक्षा II के बच्चों के लिए "यंग चिल्ड्रन रिपोर्ट कार्ड 2024" के अनुसार केवल लगभग 21.4 प्रतिशत बच्चे शब्द पढ़ने में सक्षम हैं, जबकि संख्या 99 तक पहचानने की क्षमता रखने वाले बच्चों का प्रतिशत लगभग 19.9 प्रतिशत है। ASER Annual Status of Education Report यह बताता है कि बच्चों की भाषा एवं संख्यात्मक आधारभूत क्षमता अभी भी अपेक्षित स्तर से नीचे है। निजी स्कूलों में ये प्रतिशत बेहतर हैं, लेकिन अंतर स्पष्ट है।
- **भाषाई विविधता और भाषा-माध्यम की समस्या:** राजस्थान में भाषा-उंचचपदह सर्वेक्षण द्वारा पता चला है कि अनेक जिलों में मातृभाषा और स्कूल भाषा में अंतर है। कुछ जिलों में बच्चों की मातृभाषा स्कूल में पढ़ाई भाषा से बहुत भिन्न है, जिससे भाषा अधिगम की शुरुआत में बाधाएँ आती हैं।
- **पाठ्यक्रम और सामग्री:** P2N अध्ययन के अनुसार राजस्थान में प्री-स्कूल और कक्षा 1 की पाठ्य-पुस्तकों और शिक्षण सामग्री में अनेक प्री-न्यूमेरसी गतिविधियाँ शामिल हैं, पर ग्रेड 1 में formal numeracy की अपेक्षा होती है कि बच्चे पहले से संख्या-और गिनती सम्बंधित अवधारणाएँ जानते हों। उन अवधारणाओं की प्री-स्कूल में अनुभव की निरंतरता कहीं-कहीं कम मिलती है।¹¹
- **पूर्वज्ञान एवं स्कूल प्रवेश की तैयारी:** अनेक बच्चों को स्कूल प्रारंभ करते समय पर्याप्त भाषा अनुभव, Literacy और Numeracy अनुभव घर पर नहीं मिलता, जिससे कक्षा 1 में उन्हें अतिरिक्त समर्थ की आवश्यकता होती है। यह पहलू राजस्थान में विशेष रूप से देखा गया है।¹²
- **नीतिगत और कार्यक्रमगत पहलें:** हाल ही में राजस्थान सरकार ने एक पहल शुरू की है कि लगभग 15,000 आंगनवाड़ी केंद्रों में 'प्रबोधक' (Prabodhak) शिक्षक तैनात किए जाएँ, जो 5-6 वर्ष के बच्चों को भाषा और संख्यात्मक आधार देने वाले उम्र-अनुपयुक्त पुस्तकें तथा मूल्य-आकलन प्रदान करें।¹³ इस तरह की पहल बच्चों को औपचारिक स्कूल की ओर बेहतर संक्रमण सुनिश्चित करने में मदद कर सकती है।

प्रभावी विधियाँ और सर्वोत्तम अभ्यास

राजस्थान में प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर भाषा अधिगम और संख्यात्मक क्षमता को मजबूत करने के लिए अनेक नवाचारी पहलें की गई हैं। इन पहलों ने बच्चों की सीखने की गति को बढ़ाने और शिक्षा की गुणवत्ता को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

- **भाषा-मैपिंग सर्वेक्षण और नीति निर्धारण-** राजस्थान में Language and Learning Foundation, आरएससीईआरटी, समग्र शिक्षा अभियान तथा यूनिसेफ-राजस्थान के सहयोग से भाषा-मैपिंग सर्वेक्षण किया गया। इस सर्वेक्षण ने यह तथ्य उजागर किया कि कक्षा में मौजूद भाषा-विविधता को ध्यान में रखते हुए माध्यम (Medium of Instruction – MoI) का चयन किया जाना चाहिए। बच्चों की मातृभाषा, उनकी भाषाई समझ और विद्यालय की शिक्षण भाषा के बीच संतुलन स्थापित करने से शिक्षा अधिक प्रभावी बन सकती है। इस पहल से नीति-निर्माताओं को यह स्पष्ट दिशा मिली कि बच्चों को मातृभाषा में सीखने का अवसर देकर उनकी जड़ों को मजबूत किया जाए और धीरे-धीरे विद्यालय भाषा की ओर सहज रूप से बढ़ाया जाए।¹⁴

- **संख्यात्मक क्षमता के लिए Pathways to Numeracy (P2N)**— P2N अध्ययन ने यह सुझाव दिया कि छोटे बच्चों के लिए प्री-न्यूमेरसी गतिविधियों को और मजबूत किया जाए। विशेषकर कक्षा 1 और 2 में पढ़ाई जाने वाली सामग्री बच्चों के जीवन अनुभवों से जुड़ी होनी चाहिए, ताकि गणितीय अवधारणाएँ केवल सैद्धांतिक न रहकर व्यावहारिक और रुचिकर बनें। जैसे वस्तुओं की गिनती, जोड़-घटाव को खेलों, कहानियों और गतिविधियों के माध्यम से सिखाना। इस प्रकार की शिक्षण पद्धति से बच्चों में संख्यात्मक क्षमता सहज रूप से विकसित होती है और वे गणित विषय से डरने के बजाय उसे आनंदपूर्वक अपनाते हैं।³
- **‘प्रबोधक’ शिक्षकों की भूमिका** — राजस्थान सरकार द्वारा ‘प्रबोधक’ शिक्षकों की नियुक्ति भी एक प्रभावी पहल है। ये शिक्षक आंगनबाड़ी से प्राथमिक विद्यालय में आने वाले बच्चों के संक्रमण काल को आसान बनाते हैं। वे विशेष रूप से भाषा और प्रारंभिक संख्यात्मक ज्ञान प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित होते हैं और बच्चों के लिए गतिविधि-आधारित अधिगम सामग्री का उपयोग करते हैं। इस प्रयास से छोटे बच्चों के लिए विद्यालय का वातावरण सहज बनता है और उनकी शैक्षिक यात्रा की शुरुआत मजबूत आधार पर होती है।

नीति प्रेरित उपाय और प्रस्ताव

राजस्थान राज्य की स्थिति को ध्यान में रखते हुए नीचे कुछ नीति-उपाय प्रस्तावित हैं जो भाषा अधिगम और संख्यात्मक क्षमता को बेहतर बनाने में सहायक हो सकते हैं:

1. **मातृभाषा-आधारित प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ावा देना:** भाषा-मैपिंग सर्वेक्षण के आँकड़ों के अनुसार, जहाँ संभव हो, स्कूल की पढ़ाई की शुरुआत बच्चों की मातृभाषा से करना चाहिए, विशेष रूप से पहाड़ी, आदिवासी और ग्रामीण इलाकों में। इससे भाषा की समझ में शुरुआती बाधाएँ कम होंगी।
2. **आंगनबाड़ी-स्कूल संबंधों को सुदृढ़ करना:** राज्य की ‘प्रबोधक’ शिक्षक योजना को विस्तारित करना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि आंगनबाड़ी केंद्रों में समय-समय पर मूल्य-आकलन और शिक्षण सामग्री का उपयोग हो, ताकि बच्चे स्कूल में प्रवेश करते समय बेहतर तैयार हों।
3. **प्रारंभिक संख्या अनुभवों को पाठ्यक्रम में मजबूती से शामिल करना:** प्री-स्कूल और कक्षा 1 के पाठ्यपुस्तकों में गिनती, पैटर्न, मापन, आकृतियाँ आदि गतिविधियों की संख्या बढ़ानी चाहिए, तथा बच्चों को वास्तविक जीवन की संख्यात्मक समस्याएँ अनुभव करने के अवसर प्रदान किए जाएँ।
4. **शिक्षक प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण:** शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए, विशेषकर भाषा अधिगम, मातृभाषा माध्यम शिक्षा, सक्रिय-संवादात्मक शिक्षण, और बच्चों के पूर्वज्ञान को पहचान कर शिक्षण क्रियाएँ तैयार करने की क्षमता।
5. **संसाधन और सहायक सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना:** सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में दृश्य-श्रव्य सामग्री, गिनती यंत्र, खेल-आधारित शिक्षण सामग्री, कहानियों-पठन सामग्री आदि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होनी चाहिए।
6. **निरंतर मूल्यांकन व फीडबैक:** सरकार और विद्यालय प्रबंधन को आकलन-पद्धतियों को सुधार करना चाहिए; फॉर्मेटिव मूल्यांकन होना चाहिए, जहाँ बच्चों की भाषा समझ, बोले जाने की क्षमता और संख्यात्मक सोच पर ध्यान दिया जाए।

7. **समुदाय एवं अभिभावकों की भागीदारी बढ़ाना:** ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में माता-पिता को प्रेरित करना चाहिए कि वे घरेलू भाषा में बातचीत, कहानियाँ सुनना-पढ़ना, गिनती-खेल आदि गतिविधियाँ अपने बच्चों के साथ करें। स्कूल-समुदाय भागीदारी से स्थानीय भाषा और संस्कृति को शिक्षा में शामिल करना संभव हो सकेगा।

निष्कर्ष

राजस्थान की प्राथमिक शिक्षा में भाषा अधिगम और संख्यात्मक क्षमता दोनों में सुधार की दिशा में कुछ सकारात्मक संकेत हैं। जैसे आंगनबाड़ी केंद्रों में 'प्रबोधक' शिक्षकों की तैनाती, भाषा-उंचचपदह सर्वेक्षण और P2N जैसे अध्ययनों द्वारा यह स्पष्ट करना कि किस तरह की सामग्री और पाठ्यक्रम प्रभावी हैं। फिर भी, सरकारी स्कूलों में अधिकांश बच्चों की भाषा और संख्या की मूल क्षमताएँ अभी अपेक्षाकृत कम हैं। मातृभाषा की शुरुआत, संसाधनों की समुचित उपलब्धता, शिक्षक प्रशिक्षण, अभिभावक एवं समुदाय की भागीदारी, एवं मूल्यांकन पद्धतियों में सुधार यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि राजस्थान के सभी बच्चे प्रारंभिक वर्षों में भाषा और संख्यात्मक विकास की मजबूत नींव प्राप्त करें। इस तरह की नींव उनके आगे के शैक्षिक जीवन और सामाजिक-आर्थिक अवसरों के लिए निर्णायक होगी।

संदर्भ सूची

1. <https://www.iasgyan.in/daily-current-affairs/nipun-bharat-21>
2. https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/nipun_bharat_eng1.pdf
3. <https://asercentre.org/wp-content/uploads/2022/12/Rajasthan-2.pdf>
4. <https://asercentre.org/wp-content/uploads/2022/12/Rajasthan-2.pdf?utm>
5. <https://languageandlearningfoundation.org/wp-content/uploads/2025/04/LM-Report-Rajasthan-Phase-2.pdf?utm>
6. <https://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/rajasthan-government-schools-to-implement-local-languages-in-primary-classes/articleshow/110220278.cms?utm>
7. <https://www.mle-india.net/2024/06/local-dialects-to-be-included-in.html>
8. <https://www.educationtimes.com/article/campus-beat-college-life/99735781/integration-of-local-languagesinduces-confidence-inrajasthan-students>
9. <https://languageandlearningfoundation.org/wp-content/uploads/2025/04/LM-Report-Rajasthan-Phase-2.pdf>
10. पारख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 रिपोर्ट – https://parakh.ncert.gov.in/sites/default/files/2025-07/REPORT_Rajasthan_IND008.pdf
11. <https://asercentre.org/researches/pathways-to-numeracy-p2n/>
12. चौधरी, पी. के., जोशी, आर., और कुमार, ए. (2023)। भारत में पूर्व-प्राथमिक शिक्षा तक पहुँच में क्षेत्रीय और सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ: एक हालिया घरेलू सर्वेक्षण के साक्ष्य। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन पॉलिसी, 17(1), 13.



**International Journal of Advanced Research and
Multidisciplinary Trends (IJARMT)**
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 Website: <https://ijarnt.com> ISSN No.: 3048-9458

13. <https://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/edu-dept-to-deploy-prabodhak-teachers-at-anganwadi-centres/articleshow/122844772.cms>
14. <https://languageandlearningfoundation.org/wp-content/uploads/2025/04/LM-Report-Rajasthan-Phase-1.pdf>